तमिलनाडु के पांच जिलों का भूजल क्रोमियम से प्रदूषित

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस
(1 अगस्त)

संदर्भ-

- केंद्रीय भूजल बोर्ड के सर्वेक्षण के अनुसार, तमिलनाडु के 5 जिलों में भूजल क्रोमियम (>0.05 मिलीग्राम/एलआरटी) से दूषित है जो भारतीय मानक ब्यूरो की सीमा से ऊपर है।
- क्रोमियम प्राकृतिक रूप से एक भारी धातु है जिसे आमतौर पर उद्योगों में उपयोग किया जाता है और यह मनुष्यों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है।
- यह हवा, पानी, मिट्टी और भोजन में आसानी से शामिल हो सकता है और साथ ही यह सामान्य प्रकार अर्थात इंजेक्शन, इनहेलेशन या त्वचीय संपर्क के द्वारा भी शामिल हो सकता हैं।

- इससे पहले भारत को इजराइल और 6 अन्य देशों के साथ एसटीए -2 देशों के रूप में रखा गया था।

क्रोमियम-

- यह आमतौर पर दो रूपों में पाया जाता है - त्रिकोणीय क्रोमियम (सीआर III) और हेक्सावालेन्ट क्रोमियम (सीआर VI)।
- सीआर III तत्व का सबसे स्थिर रूप है और स्वाभाविक रूप से जानवरों, पौधों, चट्टानों, और मिट्टी और गैर विषैले पदार्थों में पाया जाता है।
- सीआर VI शायद ही कभी प्राकृतिक रूप में होता है और आमतौर पर मानववंशीय गतिविधियों का उत्पाद होता है और यह न्यूरोटॉक्सिक, जीनोटॉक्सिक और कैंसरकारी होता है।
- क्रोमियम का उपयोग मिश्र धातु, अवरोधक पेंट, लकड़ी के संरक्षक और खाना पकाने के सिस्टम और बॉयलर में एंटीकोरोरोसिव के निर्माण में किया जाता है।
- वैसे उद्योग जिनका योगदान चमड़े में, धातु प्रसंस्करण में, स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग में, क्रोमेट उत्पादन में अधिक है, वहाँ भी इसका उपयोग किया जाता हैं।

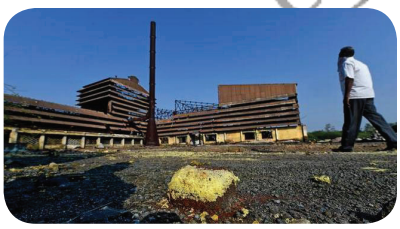

अमेरिका ने भारत को सामरिक व्यापार प्राधिकरण-1 (एसटीए-1) देश का दर्जा दिया

फाइनेंसियल एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया
(1 अगस्त)

संदर्भ-

- हाल ही में अमेरिका ने भारत को सामरिक व्यापार प्राधिकरण-1 (एसटीए- 1) देश का दर्जा देकर उसके लिए हाई-टेक प्रॉडक्ट्स की बिक्री के लिए निर्यात नियंत्रण में रियायत दे दी है।
- साथ ही अमेरिका ने पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करते हुए आईएमएफ को पाकिस्तान को राहत पैकेज देने को लेकर आगाह किया है।
- 2016 में भारत को अमेरिका के 'प्रमुख रक्षा सहयोगी' के रूप में मान्यता मिलने के बाद उसे एसटीए-1 का दर्जा हासिल हुआ है।

कौन-कौन से देश शामिल है?

- इस सूची में 36 देश शामिल हैं।
- भारत एकमात्र दक्षिण एशियाई देश है, जिसे इस सूची में शामिल किया गया है।
- अन्य एशियाई देशों में जापान और दक्षिण कोरिया शामिल है।
- अमेरिका ने इस तरह का दर्ज अपने सहयोगी नाटो देशों को दिया हुआ है।

भारत को क्या लाभ?

- भारत अमेरिका से अत्याधुनिक और संवेदनशील प्रौद्योगिकी खरीद पाएगा।
- द्विपक्षीय सुरक्षा व्यापार रिश्ते को विस्तार मिलेगा, जिसके परिणास्वरूप भारत में अमेरिका से होने वाले निर्यात में वृद्धि होगी।
- भारत को सुरक्षा एवं दूसरी हाई-टेक प्रोडक्ट्स का और बड़ा सप्लाइ चेन हासिल होगा जिससे विभिन्न अमेरिकी तंत्रों के साथ उसकी गतिवधियां बढ़ेंगी।

- दोनों देशों के सिस्टम के बीच पारस्परिकता की वृद्धि होगी।
- लाइसेंसों की स्वीकृति में समय और संसाधनों की बचत होगी।

अमेरिका को क्या लाभ?

- अमेरिकी कंपनियां भारत के उच्च तकनीक एवं सैन्य साजो-सामान बनानेवाली कंपनियों को पहले से कहीं ज्यादा रेंज के प्रोडक्ट्स निर्यात कर सकेंगी।
- इससे अमेरिकी मैन्युफैक्चरर्स को लाभ मिलेगा।
- भारत को उस प्रकार के प्रोडक्ट्स की आपूर्ति के लिहाज से अमेरिका को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ होगा।

मॉरीशस के एसबीएम को सहायक कंपनी के रूप में आरबीआई की मंजूरी

द हिन्दू
(31 जुलाई)

संदर्भ-

- मॉरीशस स्थित एसबीएम समूह की एक विदेशी बैंक को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक मार्ग के माध्यम से देश में संचालित करने के लिए आरबीआई ने मंजूरी दे दी है।

- 2013 में स्थानीय निगमन के बाद इस तरह के लाइसेंस प्राप्त करने वाला यह पहला विदेशी ऋणदाता है।
- एसबीएम, जो 1994 से भारत में है, वर्तमान में मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और रामचंद्रपुरम में चार शाखाओं के माध्यम से अपना व्यापार का संचालन कर रहा है।
- वर्तमान में, कई विदेशी बैंक देश में अपने ब्रांच के माध्यम से देश में काम कर रही हैं।

केंद्र सरकार ने सोलर सेल आयात करने पर लगाया 25वां संरक्षण शुल्क

बिजनेस स्टैण्डर्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकॉनोमिक टाइम्स
(30 जुलाई)

संदर्भ-

- हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन और मलेशिया से सोलर सेल और मॉड्यूल के आयात पर 25% संरक्षण शुल्क 2 वर्षों के लिए लगाया है।
- इसका उद्देश्य घरेलू सोलर सेल निर्माता सेक्टर की सहायता करना है।
- यह विशेष रूप से चीन से आने वाले सौर पैनलों को प्रभावित करेगा और भारत की सौर क्षमता का 85 प्रतिशत से अधिक चीनी पैनलों पर बनाया जाता है।
- इस निर्णय से उन प्रोजेक्ट्स में असर पड़ सकता है जो सस्ती सोलर उपकरण के लिए आयात पर निर्भर थे।
- भारत में सोलर पैनल में उपयोग किये जाने वाले 90% सोलर सेल चीन और मलेशिया से आयात किये जाते हैं।

क्यों लगाया जाता है यह शुल्क?

- यह शुल्क सरकार द्वारा आयात पर लगाया जाता है।
- यह शुल्क तब लागू होता जब किसी खास देश से कोई विशेष उत्पाद के आयात में वृद्धि होती है और इससे घरेलू उद्योग को भारी नुकसान होने लगता है।
- आम तौर पर यह एक अस्थायी शुल्क होता है, जिसे घरेलू सेक्टर को नुकसान की सम्भावना बचाने के लिए आयात पर लगाया जाता है।

होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक लोकसभा से पारित

बिजनेस स्टैण्डर्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया
(30 जुलाई)

संदर्भ-

- हाल ही में लोकसभा ने होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018 को मंजूरी दे दी है, अब सरकार सुनिश्चित करेगी कि सभी होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों में न्यूनतम मानदंड और बुनियादी सुविधाएं हों।
- यह होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2018 का स्थान लेगा।
- इसके लिए अध्यादेश 18 मई, 2018 को लागू किया गया था।
- सरकार होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी और सिद्धा चिकित्सा पद्धतियों पर एक अलग विधेयक भी लेकर आएगी।

उद्देश्य-

- देश में सभी होम्योपैथी कॉलेजों को मान्यता प्रदान करने में सरकार की भूमिका सुनिश्चित होगी।

विधेयक से संबंधित मुख्य तथ्य

- केंद्र सरकार को परिषद् की जगह संचालन मंडल के गठन का अधिकार दिया गया है।

GS World
Committed to Excellence

- यह किसी भी नये होम्योपैथी कॉलेजों की स्थापना, पुराने कॉलेजों में सीटें बढ़ाने या नये पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्वानुमति को अनिवार्य बनाता है।
- आयुष के सभी प्रणालियों आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी के नियमन एवं विकास के लिए एक नया अधिनियम लाने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है।
- यह एक वृहद अधिनियम होगा।
- पूर्व में चल रहे होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज अथवा कोई मेडिकल कॉलेज को नए कोर्स शुरू करने से पहले उसे केंद्र सरकार से एक वर्ष के भीतर अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- ऐसा नहीं करने पर उस कॉलेज द्वारा दी गयी डिग्री इत्यादि मान्य नहीं होगी।

इसके सदस्य-

- अधिकतम सात सदस्य होंगे तथा परिषद् के पुनर्गठन तक यह परिषद् की जिम्मेदारियाँ निभायेगा।
- इनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा करेगी।
- सरकार द्वारा सदस्यों में से ही किसी एक को अध्यक्ष चुना जायेगा।
- नीति निर्णय के सम्बन्ध में केंद्र सरकार का फैसला ही अंतिम होगा।

जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना राजस्थान

द हिन्दू
(1 अगस्त)

संदर्भ-

- हाल ही में राजस्थान इस वर्ष केंद्र द्वारा अनावरण किए गए जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
- राजस्थान अब तेल बीजों के उत्पादन में वृद्धि करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- उदयपुर में वैकल्पिक ईंधन और ऊर्जा संसाधनों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा।

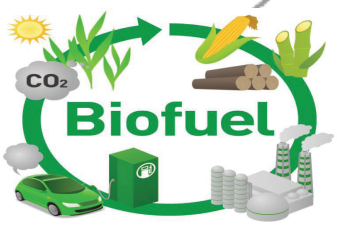

- जैव ईंधन पर नीति किसानों को आर्थिक रूप से अपने अधिशेष स्टॉक का निपटान करने और देश की तेल आयात निर्भरता को कम करने में मदद करना चाहती है।

पूर्व में उठाये गये कदम-

- भारतीय रेलवे की वित्तीय सहायता से राजस्थान में 8 टन प्रतिदिन की क्षमता का एक बायोडीजल संयंत्र पहले ही स्थापित किया जा चुका है।
- राज्य सरकार जैव ईंधन के विपणन को बढ़ावा देगी और उसके बारे में जागरुकता का प्रसार करेगी।
- राज्य ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (SRLDC) बायोडीजल की आपूर्ति के माध्यम से अतिरिक्त आय के स्त्रोतों का पता लगाने के लिए महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को भी प्रोत्साहित करेगी।

जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2018

- इसमें गन्ने का रस, चीनी युक्त सामग्री, स्टार्च युक्त सामग्री तथा क्षतिग्रस्त अनाज, जैसे- गेहूं, टूटे चावल और सड़े हुए आलू का उपयोग करके एथेनॉल उत्पादन हेतु कच्चे माल के दायरे का विस्तार किया गया है।
- प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत उचित वित्तीय और आर्थिक प्रोत्साहन बढ़ाने के उद्देश्य से इस नीति में जैव ईंधनों को आधारमुक्त जैव ईंधनों यानी पहली पीढ़ी (1जी) के बायोएथेनॉल और बायोडीजल तथा विकसित जैव ईंधनों यानी दूसरी पीढ़ी (2जी) के एथेनॉल, निगम के ठोस कचरे (एमएसडब्ल्यू) से लेकर ड्रॉप-इन ईंधन, तीसरी पीढ़ी (3जी) के जैव ईंधन, बायोसीएनजी आदि को श्रेणीबद्ध किया गया है।

नीति आयोग ने ग्लोबल मोबिलिटी हैकथॉन 'मूव हैक' का शुभारम्भ किया

फाइनेंसियल एक्सप्रेस, इकॉनोमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया
(2 अगस्त)

संदर्भ-

- हाल ही में नीति आयोग ने भारत में गतिशीलता के भविष्य के उद्देश्य से क्राउडसोर्स के लिए वैश्विक गतिशीलता हैकथॉन मूव हैक का शुभारम्भ किया है।
- इसके वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े हैकथॉन में से एक होने की परिकल्पना की गई है।

- 21वीं शताब्दी के नवाचार और आर्थिक विकास के संभावित चालकों के रूप में परिवहन और गतिशीलता उभर कर सामने आई है।
- मूव हैक 10 विषयों पर केंद्रित है और तीन स्तंभों अर्थात पहले ऑनलाइन फिर सिंगापुर और अंत में नई दिल्ली में संचालित किया जाएगा।

लक्ष्य-

- गतिशीलता से संबंधित समस्याओं के लिए अभिनव, गतिशील और मापनीयता का लक्ष्य है।

हैकथॉन के दो-आयामी अभियान दृष्टिकोण

(a) "Just Code It"- प्रौद्योगिकी/उत्पाद/सॉफ्टवेयर और डेटा विश्लेषण में, नवाचारों के माध्यम से समाधान किया जाएगा।

(b) "Just Solve It" - अभिनव व्यावसायिक विचार या टिकाऊ समाधान प्रौद्योगिकी के माध्यम से गतिशीलता बुनियादी ढांचे को बदलने पर संचालित किया जाएगा।

नोट-

- विजेताओं की घोषणा मूव सम्मेलन 2018 के दौरान की जाएगी, जो नई दिल्ली में सितंबर, 2018 में नीति आयोग द्वारा आयोजित किया जायेगा।
- हैकथॉन के लिए पुरस्कारों में शीर्ष 10 विजेताओं को मान्यता दी जायेगी, जिसमें कुल पुरस्कार राशि 2 करोड़ रुपये से अधिक है।

संबंधित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. केंद्रीय भूजल बोर्ड के सर्वेक्षण के अनुसार तमिलनाडु के कुछ जिलों के भूजल में भारतीय मानक ब्यूरो के मानक से अधिक क्रोमियम की मात्रा पायी गई है।
2. क्रोमियम एक भारी धातु है, जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

2. 'सामरिक व्यापार प्राधिकरण' के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सत्य हैं?

1. हाल ही में अमेरिका ने भारत को सामरिक व्यापार प्राधिकरण-1 देश का दर्जा प्रदान किया है।
2. अमेरिका द्वारा प्रदान सामरिक व्यापार प्राधिकरण-1 देशों की सूची में दक्षिण एशिया से केवल भारत ही शामिल है।
3. सामरिक व्यापार प्राधिकरण-1 सूची में दक्षिण-पूर्व एशिया से दक्षिण एशिया एवं जापान शामिल हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(a) 1 और 2
(b) 2 और 3
(c) 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हाल ही में एसबीएम को सहायक कम्पनी के रूप में केन्द्रीय रिजर्व बैंक द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है।
2. एसबीएस, मॉरीशस में स्थित है, जो कि भारत में अपनी चार शाखाओं (मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद और रामचंद्रपुरम) के माध्यम से व्यापार संचालित कर रही है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

4. हाल ही में भारत सरकार द्वारा सोलर सेल आयात पर लगाए गए शुल्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सत्य हैं?

1. भारत सरकार ने चीन एवं मलेशिया से आयातित सोलर सेल एवं मॉड्यूल पर 25% संरक्षण शुल्क आरोपित कर दिया है।
2. यह संरक्षण शुल्क दो वर्षों के नीचे लागू किया गया है।
3. इसका उद्देश्य घरेलू सोलर सेल निर्माता सेक्टर की सहायता करना है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(a) 1 और 2
(b) 2 और 3
(c) 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

CS World Committed To Excellence

5. हाल ही में पारित (निम्न सदन में) होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक-2018 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इसका उद्देश्य सभी होम्पोपैथी कॉलेजों को मान्यता प्रदान करने में सरकार की भूमिका सुनिश्चित करना है।
2. इसमें प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार, परिषद् के स्थान पर संचालन मंडल का गठन कर सकती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

6. जैव ईंधन नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सत्य हैं?

1. हाल ही में इसे लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है।
2. इसमें एथेनॉल उत्पादन हेतु कच्चे माल को दायरे में विस्तार किया गया है।
3. इस नीति में जैव ईंधनों को आधार युक्त जैव ईंधन अर्थात् प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी एवं तृतीय पीढ़ी के जैव ईंधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

नीच दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(a) 1 और 2
(b) 2 और 3
(c) 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

7. 'मूव हैक' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह दस विषयों पर केन्द्रित है और तीन स्तम्भों (पहला ऑनलाइन, दूसरा सिंगापुर में तीसरा नई दिल्ली) में संचालित किया जाएगा।
2. यह गतिशीलता से संबंधित समस्याओं के लिए अभिनव, गतिशील और मापनीयता का लक्ष्य लिए हुए है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

नोट-

01 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संबंधित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(a), 3(c), 4(d), 5(c), 6(d) होगा।

GS World
Committed To Excellence